

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 103/2019

1. दिनेश कुमार पुत्र रामनिवास, जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. मनोज कुमार पुत्र रामनिवास, जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनू।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अनिता स्त्री रमेश, जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनू।
2. सत्यवीर पुत्र रामनिवास
3. शान्ति स्त्री रामनिवास
4. मन्जू पुत्री रामनिवास
5. सुरेश पुत्र हुक्मराम
6. राजकुमार पुत्र हुक्मराम

जाति जाट, निवासी लोटासरो की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनू।

---रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 28.08.2019 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू मुकदमा उनवानी श्रीमती अनिता बनाम दिनेश वगैरह मु0न0 05/2019 अ0धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मो0 फारुक, एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.07.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.08.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट निम्न प्रकार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2019 खिलाफ कानून न्याय एवं पत्रावली है मौजूदा प्रकरण अनिता स्त्री रमेशकुमार जाति जाट निवासी लोटासरा की ढाणी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 पर दर्ज हुआ है। अनिता स्त्री रमेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 में यह दर्ज नहीं किया की वह कौनसे गांव की सीमा में कौनसे खसरा नम्बर की खातेदार है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 उक्त शिकायत कर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा कि उनकी कौनसे खसरा नम्बर की जमीन के वे खातेदार है तथा कौनसे खसरा नम्बर में किस व्यक्ति ने रास्ता तथाकथित रूप से अवरुद्ध किया है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण अदालत मातहत ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत क्यों दर्ज किया स्पष्ट नहीं है। इस कारण मौजूदा प्रकरण में धारा 215 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण आलौच्य निर्णय खारीज किया जाना न्यायोचित है। मौजूदा प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि तथाकथित रूप से रास्ता ख0न0 248 ग्राम लोटासरा की ढाणी में अवरुद्ध किया है या ख0न0 249 में ख0न0 249 की किस्म गैर मुमकीन आबादी है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान गैर मुमकीन आबादी भूमि पर लागू नहीं होते। जमीन हाल ख0न0 229, 228, 227 ग्राम लोटासरा की ढाणी

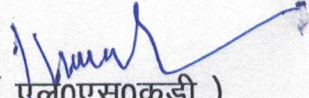
की खातेदार अनिता स्त्री रमेश नहीं है। कानून से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सिर्फ अवरुद्ध रास्ता खुलवाने के लिये खातेदार ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। ख0न0 229 व 227 की जमीन के पहले से एक कदीमी चालू रास्ता ख0न0 227 की पूर्वी दिशा से औला की ढाणी से रास्ता आने जाने के लिये मौजूद है जो चालू है शिकायत कर्ता उक्त रास्ता का ही उपयोग व उपभोग करते हैं ख0न0 248 से शिकायत कर्ता का कभी आने जाने का रास्ता नहीं रहा। इस कारण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नहीं खोला जा सकता। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 में लिखा है कि उक्त तथाकथित रास्ता को अनिता स्त्री दलीप व नरेन्द्र पुत्र विद्याधर ने अवरुद्ध किया है जबकि प्रकरण में अनिता स्त्री दलीप एवं नरेन्द्र पुत्र विद्याधर को पक्षकार नहीं बनाया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स की जबाब देही को गलत रूप से नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। आलौच्य निर्णय स्पष्ट नहीं है तथा आलौच्य निर्णय पारित करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। निर्णय में सभी पक्षकारों का नाम दर्ज नहीं किया। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि मौजूदा प्रकरण अनिता स्त्री रमेशकुमार जाति जाट निवासी लोटासरा की ढाणी के प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 पर दर्ज हुआ है। अनिता स्त्री रमेश ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2019 में यह दर्ज नहीं किया की वह कौनसे गांव की सीमा में कौनसे खसरा नम्बर की खातेदार है। रेस्पोंडेन्ट नं0 1 उक्त शिकायत कर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह नहीं लिखा कि उनकी कौनसे खसरा नम्बर की जमीन के वे खातेदार है तथा कौनसे खसरा नम्बर में किस व्यक्ति ने रास्ता तथाकथित रूप से अवरुद्ध किया है। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण अदालत मातहत ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत क्यों दर्ज किया स्पष्ट नहीं है। इस कारण मौजूदा प्रकरण में धारा 215 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण आलौच्य निर्णय खारीज किया जाना न्यायोचित है। मौजूदा प्रकरण में यह स्पष्ट नहीं है कि तथाकथित रूप से रास्ता ख0न0 248 ग्राम लोटासरा की ढाणी में अवरुद्ध किया है या ख0न0 249 में ख0न0 249 की किस्म गैर मुमकीन आबादी है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान गैर मुमकीन आबादी भूमि पर लागू नहीं होते। जमीन हाल ख0न0 229, 228, 227 ग्राम लोटासरा की ढाणी की खातेदार अनिता स्त्री रमेश नहीं है। कानून से धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सिर्फ अवरुद्ध रास्ता खुलवाने के लिये खातेदार ही प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। ख0न0 229 व 227 की जमीन के पहले से एक कदीमी चालू रास्ता ख0न0 227 की पूर्वी दिशा से औला की ढाणी से रास्ता आने जाने के लिये मौजूद है जो चालू है शिकायत कर्ता उक्त रास्ता का ही उपयोग व उपभोग करते हैं ख0न0 248 से शिकायत कर्ता का कभी आने जाने का रास्ता नहीं रहा। इस कारण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता नहीं खोला जा सकता। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.05.2019 में लिखा है कि उक्त तथाकथित रास्ता को अनिता स्त्री दलीप व नरेन्द्र पुत्र विद्याधर ने अवरुद्ध किया है जबकि प्रकरण में अनिता स्त्री दलीप एवं नरेन्द्र पुत्र विद्याधर को पक्षकार नहीं बनाया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स की जबाब देही को गलत रूप से नजर अन्दाज कर आलौच्य निर्णय पारित किया है। आलौच्य निर्णय स्पष्ट नहीं है तथा आलौच्य निर्णय पारित करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। निर्णय में सभी पक्षकारों का नाम दर्ज नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 28.08.2019 निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पॉडेन्ट सं० 1 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश विधिसम्मत है। विवादित भूमि के मौके पर पक्की सडक बनी हुई है जिसे अपीलान्ट ने छडी वगैरह डालकर बन्द कर दिया था। मौके पर बन्द रास्ते को खुलवाया गया है। उक्त सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। अपीलान्ट को सडक व रास्ते को रोकने का कोई हक नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि के मौके पर सडक बनी हुई है। अपीलान्ट ने रास्ते व सडक को छडी डालकर बन्द किया है। उक्त सडक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है। अदालत मातहत ने उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलान्ट सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। मौके पर रास्ता खुला रहेगा। अपील खारिज होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल०एस०कुडी)
जिला कलक्टर,
जिला झुंझुनूं